फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 110 प्रभात जयपुर, गुरुवार 21 नवम्बर, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

# राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

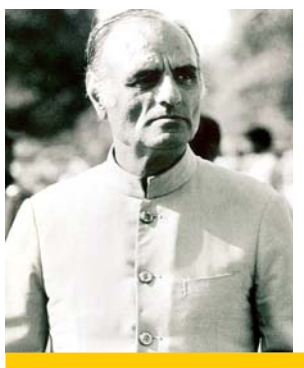

**Honest, Decisive but not a Hermit**

Pahadia's legendary inefficiency forced the centre to depute Wali. All formalities were over, but the CMs orders, appointing him as Chief Secretary, had still not been signed by midnight.

**The truth isn't just out there - it's in you!**

# महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दिखी पंचायत चुनावों की झलक

## आम मतदाता ना महायुति के लोक लुभावन वादों से प्रभावित नज़र आया, ना ही महाविकास अघाड़ी के मराठी अस्मिता के भावनात्मक मुद्दे से सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही हावी रहे

- लक्ष्मण वैंकट कुची -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। महाराष्ट्र में मतदान सम्पन्न हो गया है। राज्य के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का भाग्य ई.वी.एम. में सीलबन्द हो गया है। आईये, एक नजर इस तथ्य पर डालें कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान यह चुनावी लड़ाई कैसे लड़ी गई।

जहाँ भाजपा, शिवसेना (शिन्दे) तथा एन.सी.पी (अजित पवार) से मिलकर बना सत्तारूढ़ गठबन्धन "महायुति" प्रतिस्पर्धी लोकप्रियता, रेवड़ी कल्चर, विकास और ग्रोथ के वादों तथा इन सबसे ऊपर आक्रामक हिन्दुत्व के मिश्रण पर निर्भर है, वहीं विपक्ष ने क्रॉनी कैपिटलिज़्म, मराठी अस्मिता, रोटी-कपड़ा-मकान की बुनियादी जरूरत, आजीविका, रोजगार तथा दैनिक उपयोग की चीजों की कीमतों में भारी उछाल को सोमवार शाम को समाप्त हुये चुनाव-प्रचार का निशाना बनाया है।

सबसे पहले, सत्तारूढ़ डबल इंजन सरकार का प्रचार का नेतृत्व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह के साथ ही, योगी आदित्यनाथ, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री स्मृति ईरानी तथा कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहान जैस स्टार प्रचारकों के समूह के नेतृत्व में चला।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी और एम.एस.पी. बड़ा मुद्दा है, इन क्षेत्रों में महायुति सरकार की लोकलुभावन योजनाओं से भी जनता प्रभावित नहीं हुई।
- स्थानीय जनता ने महाविकास अघाड़ी के मराठी अस्मिता मुद्दे को भी स्वीकार नहीं किया है। महाविकास अघाड़ी ने भाजपा पर महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया है।
- भाजपा वादों को पूरा करने की गारंटी पर वोट हासिल करने की उम्मीद कर रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन ने भी क्रोनी कैपिटलिज़्म, महंगाई, बेरोजगारी व मराठी अस्मिता के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है।

मई में हुए लोक सभा चुनावों में भाजपा और महायुति की स्थिति अपेक्षाओं से उलट रहने के कारण, इस त्रिदलीय गठबन्धन ने विपक्ष के भावनात्मक मुद्दों को काटने के लिये अपने मुद्दों में बदलाव किया। लोकसभा चुनाव प्रचार में, विपक्ष ने कहा था कि भाजपा ने किस प्रकार महाराष्ट्र के दो क्षेत्रीय दलों को तोड़ दिया (जिसने मराठी भावना एवं गौरव को सीधा प्रभावित किया) तथा इसके साथ ही, विपक्ष ने व्यावहारिक, प्रगतिशील, गरीब- समर्थक एवं महिला- समर्थक तथा इनके कल्याण पर जोर दिया।

विधानसभा प्रचार में, सत्तारूढ़ गठबन्धन ने कहा कि "माझी लड़की योजना" पर "लाड़ली बहना योजना" की तर्ज पर करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि मध्यप्रदेश विधान सभा चुनावों में "लाड़ली बहना योजना" बहुत ज्यादा सफल सिद्ध हुई थी। इसके अलावा, युवाओं तथा बेरोजगारों की लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की गईं, जबकि प्रधानमन्त्री ने पहले, इन्हें "रेवड़ियाँ" मानते हुये, खारिज कर दिया था। लेकिन, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज माना जाता है, और यह चुनावी लड़ाई किसी भी महायुद्ध से कम नहीं थी। इस महायुद्ध की अन्तिम परिणति आज मतदान का रूप ले चुकी है।

महाराष्ट्र की सभी 288 विधान सभा सीटों के लिये मतगणना 23 नवम्बर, शनिवार को होनी है। इस दिन झरखंड विधान सभा चुनावों तथा विभिन्न राज्यों के बहुत से उपचुनावों के लिये मतगणना भी होनी है। मुफ्त की रेवड़ियों के मुद्दे को भाजपा नेताओं तथा महायुति- पार्टनरों ने पूरे जोश-खरोश से जनता के समक्ष रखा। जनता तक यह बात पहुँचाने में इन नेताओं ने अथक मेहनत की कि "हमारी सरकार अपने वादों को जमीन पर उतारती है, पूरा करती है।" इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं को डराया भी था कि "अगर

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## मणिपुर की "इनर लाइन परमिट" व्यवस्था को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिज़ोरम के बाद, मणिपुर ऐसा चौथा राज्य है, जहाँ आई.एल.पी. व्यवस्था लागू है। आई.एल.पी शासन- व्यवस्था वाले राज्यों में जाने वाले बाहरी लोगों, जिनमें देश के अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं, को अनुमति लेनी की आवश्यकता होती है।

- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा।
- उत्तर पूर्व के अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिज़ोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिये मणिपुर सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया है, जिस याचिका में राज्य के "इनर लाइन परमिट" आई.एल.पी. को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय तथा एस.वी.एन. भट्टी की बैंच ने राज्य सरकार के वकील की मांग पर मणिपुर

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# क्या राष्ट्रपति मुर्मू पूर्व राष्ट्रपति कोविंद द्वारा स्थापित परिपाटी पलटेंगी?

## राष्ट्रपति कोविंद के समक्ष 6 माफी याचिका प्रस्तुत की गई थीं, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए, उन्होंने छः की छः याचिका खारिज कर दी थीं

- श्रीनन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस प्रथा को तोड़ देंगी, जो उनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दया-याचना याचिकाओं को अस्वीकार करके स्थापित की थी। यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम के प्रकाश में प्रासंगिक हो गया है, जिसमें अदालत ने बलवन्त सिंह राजोना की अपील पर दो सप्ताह में निर्णय लिये उनसे कहा है। ज्ञातव्य है कि बलवन्त सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमन्त्री बेअन्त सिंह की हत्या का दोषी है। 2019 में, गुरूनानक देव की550 वीं जयन्ती के अवसर पर, सरकार ने राजोआना के मृत्यु दंड को कम करने का निश्चय किया था। जेल में 28 वर्ष बिता देने के बाद, रोजाना अब रिहाई का अनुरोध कर रहा है।

भारत 1950 में जब से गणतन्त्र बना है, विभिन्न राष्ट्रपतियों के समक्ष 440 दया-याचिकाएं प्रस्तुत हुई हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या (308) में ये याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं तथा सम्बन्धित अपराधियों के मृत्यु-दंड

- राष्ट्रपति मुर्मू के समक्ष पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की याचिका प्रस्तुत की गई है।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस याचिका पर दो सप्ताह में निर्णय लेने के लिए समय दिया है।
- 1950 से अभी तक राष्ट्रपति के समक्ष 440 माफी याचिकाएं प्रस्तुत की गई है, मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए, राष्ट्रपति ने इन याचिकाओं में से अधिकतर (308) याचिकाओं में यह परिवर्तन करने की अपील स्वीकार की है।

आजीवन कारावास में बदल दिये गये हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 181 दया-याचिकाएं प्राप्त हुई थीं तथा उन्होंने इनमें से केवल एक याचिका को अस्वीकार किया था तथा 180 याचिकाएं स्वीकार कर ली थीं तथा मृत्यु-दंड आजीवन कारावास में बदल दिये गये थे। इसके बाद, राष्ट्रपति एस.राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन तथा वी.वी. गिरी को क्रमशः 57, 22 तथा 3 दया-याचिकाएं प्राप्त हुई थी। इन तीनों राष्ट्रपतियों ने प्राप्त सभी याचिकाओं के मृत्युदंड को कम कर के आजीवन कारावास में बदल दिया था। ज्ञानी जैल सिंह को 32 याचिकाएं प्राप्त हुई लेकिन उन्होंने केवल दो याचिकाएं ही स्वीकार की तथा 30 याचिकाएं अस्वीकार कर दी थीं। अगले राष्ट्रपति आर. वैंकटरमण ने भी 50 में से 45 याचिकाएं खारिज कर दीं। देश के चौथे तथा पांचवें राष्ट्रपतियों, फखरूद्दीन

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# गुड़गाँव में कर्मचारियों पर "वर्क फ्रॉम होम" कानून लागू होगा

- जाल खंबाता-
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। गुरूग्राम जिला प्रशासन ने सभी निजी संस्थानों और कॉरपोरेट आफिसों को सलाह दी है कि वे 20 नवम्बर से अगले आदेश तक अपने आधे कर्मचारियों को वर्क फॉम होम का निर्देश दें। ऐसा करने से इससे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता कायम करने में मदद मिलेगी।

- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा किसी सरकारी या कारपोरेट संस्था के 50 प्रतिशत कर्मचारी इस निर्देश की पालना करें।
- मंत्री के अनुसार, दिल्ली में सुबह सात बजे ए.क्यू.आई. 462 थी, तथा सबसे प्रदूषित क्षेत्र थे, मुण्डका (464), वजीरपुर (462) व अतिपुर (462) तथा, इन्दिरा गाँधी एयर पोर्ट पर विजिबिलिटी केवल 800 मीटर थी।

जिला प्रशासन ने कहा कि दिल्ली एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण का असर कर्मचारियों पर भी देखा जा रहा है। गुरूग्राम के सभी निजी एवं कारपोरेट संस्थानों ने वर्क फ्रॉम होम का निर्देश जारी कर दिया है।

जिला प्रशासन की एडवाइज़री कहती है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमैंट (एन.सी.आर.) के निर्देशों के अनुरूप गुरूग्राम के सभी निजी एवं कॉरपोरेट संस्थान 50 प्रतिशत वर्क फॉर होम पॉलिसी पर काम रहे थे। वायु की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

दिल्ली की एयर क्वालिटी इन्डैक्स बुधवार को भी गंभीर श्रेणी में रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की कि राज्य सरकार के 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली में मुंडका सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा।

मंत्री के अनुसार, दिल्ली में सुबह सात बजे एम.क्यू.आई. 462 थी, तथा सबसे प्रदूषित क्षेत्र थे, मुण्डका (464), वजीरपुर (462) व अतिपुर (462) तथा, इन्दिरा गाँधी एयर पोर्ट पर विजिबिलिटी केवल 800 मीटर थी।

## चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश पर रोक

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मेडिकल काउन्सिल के गत 6 नवंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत आर.एम.सी. ने सरकारी सेवा में कार्यरत याचिकाकर्ता चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव और आर.एम.सी. के

- याचिकाकर्ता ने कहा, उसने नेपाल से एम.बी.बी.एस. किया, 2013 में फॉरेन मेडीकल परीक्षा पास की, आर.जी.एस. सी. से चयन के बाद कई साल से कार्यरत है। राजस्थान मेडिकल काउन्सिल ने 6 नवम्बर को उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया।

रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने ये आदेश डॉ. एस.ए. इकबाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस.

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ऑर्गन ट्रांसप्लांट : चिकित्सक को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली

जयपुर, 20 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी एन.ओ.सी. से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से जुड़े मामले में फोर्टिस अस्पताल के चिकित्सक ज्योति बंसल को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए पेश विशेष अनुमति

- सर्वोच्च न्यायालय ने फोर्टिस अस्पताल के चिकित्सक, डा. ज्योति बंसल की अग्रिम जमानत के लिए पेश विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस टी.सी. रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। अदालत ने कहा कि ये अपराध चिकित्सीय नैतिकता, टोहो अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून की गंभीर अवहेलना है।

एस.एल.पी. में कहा गया कि एस.ओ.जी. को मामले में याचिकाकर्ता

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# दिल्ली के पुराने थर्मल पावर प्लांट्स पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती सरकार?

## भारतीय किसान संघ ने एक रिसर्च को आधार बना कर दावा किया कि, ये पावर प्लांट्स, "स्टबल बर्निंग" से सोलह गुना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं दिल्ली के वातावरण में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। भारतीय किसान संघ ने बुधवार को सैंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एण्ड क्लीन एयर (सी.आर.ई.ए.) की दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट्स से पराली जलाने की तुलना में 16 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है उन्होंने हैरानी जताई कि इन प्लांट्स पर रोक क्यों नहीं लगाई गई।

भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय प्रमुख राघवेन्द्र सिंह पटेल ने कहा कि (सी.आर.ई.ए.) का अध्ययन बताता है कि नैशनल कैपिटल रीजन में जो कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट्स हैं उन्होंने जून 2022 से मई 2023 के बीच 281 किलो टन सल्फर डाई-आक्साइड वातावरण में छोड़ी थी, जो कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा थी, फिर भी

- सैंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एण्ड क्लिक एनर्जी (सी.आर.ई.ए.), के अध्ययन के अनुसार राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) में लगे कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स एक लाख 281 किलो टन सल्फर डाई ऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, सल्फर डाई ऑक्साइड का प्रदूषण फैलाने की दृष्टि से।
- सरकार को इन थर्मल पावर प्लांट्स के रख-रखाव व काम काज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये, बनिस्पत किसानों द्वारा, फसल काटने के बाद बचे "स्टबल" जलाने को प्रदूषण का कारण बताने के बजाय।
- किसान संघ ने यह भी दावा किया कि, कृषि विश्वविद्यालय भी फसल कटने के बाद बचे "ठूंठ" (स्टबल) को जलाने का समर्थन करता है, क्योंकि, "स्टबल" जलाने से फसल में लगे कीड़े व अन्य हानिकारक जीवाणु/जर्म्स भी जल जाते हैं, जिससे आने वाली फसल ज्यादा स्वस्थ व किटाणु रहित रहती है।

सरकार पराली जलाने के लिए किसानों को परेशान करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को थर्मल पावर प्लांट्स पर भी कड़ा नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि विश्व विद्यालय पराली जलाने की बात कहते हैं क्योंकि इससे वे कीट मर जाते हैं जो भविष्य में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कृषि विश्वविद्यालयों के रिसर्च संस्थानों को किसानों को प्रशिक्षित करने में मदद करें और उन्हें पराली नष्ट करने के तरीके बताए।

# एग्ज़िट पोल्स ने महाराष्ट्र व झारखंड में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की

## महाराष्ट्र में भाजपा के गठबंधन को 122 से 182 सीटें मिलने और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की भविष्यवाणी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। कई एग्ज़िट पोल सर्वे यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शिवसेना (शिन्दे)- भाजपा - एन.सी.पी. (अजित पवार) का "महायुति" गठबंधन बहुमत हासिल कर सकता है और गठबंधन को 122 से 186 तक सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में भी एग्ज़िट पोल भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

कांग्रेस ने एग्ज़िट पोल निष्कर्षों को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि वह 23 नवंबर को होने वाली मतगणना का इंतज़ार करेगी।

कई चुनाव विश्लेषकों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाले एन.सी.पी. घटक तथा भारतीय जनता

- एग्ज़िट पोल में महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन महायुति को 137 से 182 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है वहीं कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी को 97 से 146 के बीच सीटे मिलने की संभावना जताई गई है।
- एग्ज़िट पोल ने झारखंड में भी भाजपा गठबंधन के जीतने की भविष्यवाणी की है। राज्य की कुल 68 सीटों में से भाजपा खेमे को 40 से 53 सीटें मिल सकती हैं वहीं कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों को 25 से 40 के बीच सीटें मिलने की बात कही गई है।
- कांग्रेस ने एग्ज़िट पोल नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, वास्तविक स्थिति 23 नवम्बर को चुनाव नतीजे आने के बाद स्पष्ट होगी।

पार्टी वाले महायुति गठबंधन, के लिए "महाजीत" की भविष्यवाणी की है। इन चुनावों के लिए आज (बुधवार) मतदान हुआ, जबकि, इसकी मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम भी इसी दिन आएंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं तथा राज्य में सरकार का गठन करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 145 सीटों की आवश्यकता होगी।

भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं, शिवसेना (शिंदे) 81 और अजित पवार के नतृत्व वाली एन.सी.पी. ने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं।

इनमें से एक सीट पर महायुति के दो प्रत्यासी आमने सामने हैं। विपक्षी गठबंधन, महा विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) में कांग्रेस ने 101 प्रत्याशी, शिवसेना (यू.बी.टी.) ने 95 और एन.सी.पी. (एस.पी.) ने 86 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं।

पीपल्स पल्स का एग्ज़िट पोल महायुति को 182 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महा विकास अघाड़ी गठबंधन को 97 सीटें तथा अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने की बात कर रहा है।

**कुछ अन्य एग्ज़िट पोल्स की भविष्यवाणियाँ इस प्रकार हैं :**

**मात्रीस :**

| | |
|---|---|
| महायुति (भाजपा +) | : 150- 170 |
| एम.वी.ए. (कांग्रेस +) | : 110-130 |
| अन्य | : 8-10 |

**पी-मार्क**

| | |
|---|---|
| महायुति (भाजपा +) | : 137-157 |
| एम.वी.ए. (कांग्रेस +) | : 126- 146 |
| अन्य | : 2-8 |

**न्यूज 24- चाणक्य**

| | |
|---|---|
| महायुति (भाजपा +) | : 152- 160 |
| एम.वी.ए. (कांग्रेस +) | : 130- 138 |
| अन्य | : 6-8 |

झारखंड में, चुनाव विश्लेषकों के अनुसार, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन सत्ता से बाहर हो सकते हैं और भाजपा गठबंधन के लिए

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## बार एसोसिएशन चुनाव में 5804 शपथ पत्र पेश

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट सहित, प्रदेश की अन्य अदालतों की बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। हाईकोर्ट बार की चुनाव संचालन समिति ने चुनाव

- चुनाव समिति ने 'वन बार वन वोट' को लेकर 12 नवम्बर से 20 नवम्बर तक अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अपना शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा था।

कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

हाईकोर्ट बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता राजीव शर्मा, राजेश कर्नल और गजेंद्र सिंह राठौड़ को

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )